

समक्ष पी. सी. जैन और जे. एम. टंडन, न्यायमूर्ति।

जगमोहन लाल वर्मा- याचिकाकर्ता।

बनाम

टेक्सटाईल कमिश्नर और अन्य- उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका संख्या 1973 की 2498।

15 दिसंबर, 1978।

आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955 का 10)-धारा 3-ऊनी वस्त्र (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण 1 आदेश, 1962-खंड 2 (घ) (च) और 3-केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944- नियम 174-भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 14 और 19 (1) (g)- सबसे खराब धागे के निर्माण में सक्षम अनधिकृत सूती परिवर्तित स्पिंडल की स्थापना-अनाधिकृत सबसे खराब स्पिंडल को नियमित करने के लिए शर्तें निर्धारित करना- अनधिकृत कपास परिवर्तित स्पिंडल-क्या प्रेस नोट के तहत नियमित करने का हकदार है-नियंत्रण आदेश के खंड 3 (1) और नियम 174 के लिए दूसरा परंतुक-क्या अनुच्छेद 14 और 19 (1) (g).

अभिनिर्धारित किया गया कि यह बहुत स्पष्ट है कि ऊनी वस्त्र (उत्पादन और वितरण नियंत्रण आदेश, 1962 का खंड 3 (1) केवल मूल खराब किए गए तकियों तक ही सीमित नहीं है। ऑर्डर सबसे खराब धागे के निर्माण में सक्षम मूल सबसे खराब स्पिंडल या परिवर्तित सूती स्पिंडल के बारे में चुप है। जैसा कि आदेश ऊनी कपड़ों से संबंधित है, खंड 3 के उप-खंड (1) के तहत 'स्पिंडल' शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से सबसे खराब धागे सहित ऊनी धागे का निर्माण करने में सक्षम होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस उपखंड में परिवर्तित सूती स्पिंडल भी शामिल होंगे जो सबसे खराब धागे का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। इसलिए, कपड़ा आयुक्त आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) के तहत बिजली निर्माण ऊनी खराब धागे द्वारा काम किए गए किसी भी स्पिंडल के लिए अनुमति देने के लिए सक्षम है, चाहे वह मूल खराब धागे वाला स्पिंडल हो या खराब धागे के निर्माण में सक्षम परिवर्तित सूती स्पिंडल हो। प्रेस नोट जो आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) में निहित प्रावधान की पुनरावृत्ति के साथ शुरू होता है, उसके बराबर है जो मूल खराब स्पिंडल और परिवर्तित सूती स्पिंडल दोनों पर लागू होता है जो खराब धागे का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह अनुमान लगाना उचित होगा कि एक गिल बॉक्स के साथ परिवर्तित सूती स्पिंडल को भी प्रेस नोट द्वारा कवर करने का इरादा था क्योंकि वे सबसे खराब धागे का उत्पादन करते हैं। इसलिए कपड़ा आयुक्त इस आधार पर सबसे खराब धागे का निर्माण करने वाले अनधिकृत परिवर्तित सूती स्पिंडल को नियमित करने से इनकार नहीं कर सकता था कि वे मूल रूप से सबसे खराब स्पिंडल नहीं थे।

(पैरा 12 और 15)

अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कार्यकारी प्राधिकारी को एक पूर्ण, दिशाहीन और अनियंत्रित शक्ति प्रदान की जाती है, तो मनमाने तरीके से इसके प्रयोग के परिणामस्वरूप भेदभाव होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नियंत्रण आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) के तहत आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी किया गया है, लेकिन अधिनियम की प्रस्तावना के साथ-साथ इसकी धारा 3 में आक्षेपित उपखंड के तहत कपड़ा आयुक्त द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश नहीं दिए गए हैं। कपड़ा आयुक्त, जो विवादित उपखंड के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम है, निस्संदेह उच्च पद का अधिकारी है, लेकिन कपड़ा आयुक्त की शक्तियां अन्य अधिकारियों के पदानुक्रम में पदेन रूप से निहित की जा सकती हैं और किसी भी रैंक के किसी भी अधिकारी को कपड़ा आयुक्त की शक्ति दी जा सकती है। केवल यह तथ्य कि खंड 3 के उपखंड (1) के अधीन वस्त्र आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील का उपबंध है, कोई अंतर नहीं लाएगा क्योंकि यह खंड 3 के अधीन प्राधिकारी के प्रयोग पर पर्याप्त रोक नहीं होगा। नियंत्रण आदेश के खंड 3 का उपखंड (1) भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 14

और 19 (1) (छ) का उल्लंघन करता है और इसके अधिकार से बाहर है क्योंकि यह वस्त्र आयुक्त को निर्देशित और पूर्ण शक्तियां देता है।

(पैरा 25 से 28)

अभिनिर्धारित किया गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 174 का दूसरा परन्तुक नियंत्रण आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) के अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह परन्तुक आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) से जुड़ा हुआ है और इसे इससे अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) से स्वतंत्र है तो आक्षेपित परन्तुक संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (छ) का भी उल्लंघन करता है और आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) जैसी मार्गदर्शक पंक्तियों के अभाव में अलग रखा जा सकता है।

(पैरा 29)

मामला 27 फरवरी, 1974 को माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. आर. शर्मा द्वारा विधि के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक वृहद पीठ को निर्दिष्ट किया गया। मामला. माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम चंद जैन और माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. एम. टंडन की खंडपीठ ने अंततः 15 दिसंबर, 1978 को मामले का फैसला सुनाया।

याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन यह प्रार्थना करते हुए कि मामले के अभिलेख भेजे जाएं और-(क) प्रत्यर्थी संख्या 1 का दिनांक 13 मार्च, 1973 का आदेश, याचिका का अनुलग्नक 'घ' अपास्त किया जाए और उक्त प्रत्यर्थी को प्रेस नोट अनुलग्नक 'ख' के अनुसार 2212 स्पिंडलों को नियमित करने का निर्देश दिया जाए।

(ख) प्रत्यर्थी संख्या 3 को लाइसेंस को निरस्त करके दिनांक 23 जुलाई, 1973 के अनुलग्नक 'जी' को प्रभावी बनाने से रोकें; और (ग) कोई अन्य राहत प्रदान करें जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर हकदार हो।

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि याचिका का निर्णय लंबित रहने तक प्रतिवादी नं. 3 एल 4 लाइसेंस को रद्द करने से रोका जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील भागीरथ दास, एस. के. हीराजी और बी. के. गुप्ता उनके साथ अधिवक्ता हैं।

कुलदीप सिंह, बार-एट-लॉ

प्रतिवादियों की ओर से जे. एल. गुप्ता, अधिवक्ता।

(1) यह आदेश 39 रिट याचिकाओं (1972 की यू डब्ल्यू एफ संख्या 3605 और 3606, 2039, 2231, 2498, 2499, 2555, 2556, 2724, 2877, 8131, 8436, 8440, 8791 और 1973 की 8835, 862, 743, 1784, 1897, 2019, 3880 और 1974 की 4380, 763, 1609, 1957, 5381, 6320, 6321, 6631, 6633, 7269, 7270, 7312 और 1975 की 7537, 304, 5539, 7395, 7595 और 1976 की 8387 जिसमें समान कानूनी बिंदु शामिल हैं, का निपटान करेगा।

2. 1973 के सी. डब्ल्यू. संख्या 2498 के तथ्यों को सभी रिट याचिकाओं में मुद्दे के बिंदुओं को उजागर करने के लिए कहा जा सकता है।

3. याचिकाकर्ता, जो मेसर्स कैप्टन वूलेन मिल्स के एकमात्र मालिक हैं, ने 1 जुलाई, 1968 से ऊनी खराब धागे का उत्पादन शुरू किया और उस उद्देश्य के लिए गिल बॉक्स, इंटरसेक्टिंग गिल बॉक्स और अन्य आवश्यक घटकों के साथ 2212 स्पिंडल स्थापित किए। सबसे खराब धागा एक हटाने योग्य लेख है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 174 (जिसे इसके बाद नियम कहा गया है) के तहत इसके निर्माण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता ने इस तरह के लाइसेंस के लिए आवेदन किया और इसे 28 मई, 1968 को प्राप्त किया। याचिकाकर्ता के पास 31 मार्च, 1973 तक लाइसेंस था और उसने अपने द्वारा उत्पादित सबसे खराब धागे पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया।

4. ऊनी वस्त्र (उत्पादन और वितरण नियंत्रण आदेश, 1962 (जिसे इसके बाद आदेश के रूप में संदर्भित किया गया है) कपड़ा आयुक्त की लिखित पूर्व अनुमति के बिना बिजली द्वारा काम किए गए किसी भी तकले के अधिग्रहण या स्थापना या बिक्री या निपटान और स्थान परिवर्तन और खराब धागे के निर्माण के लिए इसके उपयोग को प्रतिबंधित करता है। यह आदेश के खंड 3 में इस प्रकार प्रदान किया गया है। याचिकाकर्ता ने सबसे खराब धागे के निर्माण के लिए स्पिंडल की स्थापना और उपयोग के लिए कपड़ा आयुक्त से अपेक्षित अनुमति नहीं ली, जो आदेश के खंड 2 (च) में दी गई "ऊनी धागे" की परिभाषा में शामिल है। कई अन्य दलों ने इसी तरह अनधिकृत स्पिंडल लगाए थे और उन पर काम किया था। नियमों के नियम 174 के तहत लाइसेंस अनधिकृत स्पिंडल के संबंध में जारी किया जाता रहा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसके मालिकों को इसकी मांग करने से रोकता हो। नियम के नियम 174 के दूसरे परंतुक में 1971 में संशोधन किया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि ऊनी धागे (खराब धागे सहित) के निर्माण के लिए कोई लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पार्टी के पास स्पिंडल की स्थापना और काम करने के लिए कपड़ा आयुक्त की लिखित अनुमति न हो। वस्त्र आयुक्त ने 17.1971 फरवरी को एक प्रेस नोट (अनुलग्नक 'ख' की प्रतिलिपि) जारी किया, जिसमें 15 मार्च, 1971 से पहले नियमितीकरण के लिए आवेदन करने और उसमें उल्लिखित कुछ शर्तों के अधीन उन्हें नियमित करने की पेशकश करने के लिए अनधिकृत रूप से खराब धागे के स्पिंडल स्थापित करने वाले पक्षों को आमंत्रित किया गया। याचिकाकर्ता ने निर्धारित अवधि के भीतर अपने अनधिकृत स्पिंडल को नियमित करने के लिए आवेदन किया। एक विभागीय अध्ययन दल ने जुलाई, 1971 के मध्य में याचिकाकर्ता की स्थापना का निरीक्षण किया। याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था-13 मार्च, 1973 के संचार के माध्यम से, कि प्रेस नोट के तहत दिए गए नियमितीकरण का लाभ उन्हें नहीं दिया जा सकता था क्योंकि लगाए गए स्पिंडल कपास में परिवर्तित थे, जबकि प्रेस नोट में अनधिकृत खराब स्पिंडल के नियमितीकरण का प्रावधान किया गया था। दूसरे शब्दों में, अधिकारियों के अनुसार, सबसे खराब धागे का निर्माण करने वाले अनधिकृत परिवर्तित सूती स्पिंडल प्रेस नोट के संदर्भ में नियमित करने के लिए अनधिकृत सबसे खराब स्पिंडल के रूप में योग्य नहीं थे। याचिकाकर्ता ने कपड़ा आयुक्त के अपने स्पिंडल को नियमित करने से इनकार करने के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी है कि प्रेस नोट में सबसे खराब धागे के स्पिंडल और सबसे खराब धागे के निर्माण में सक्षम परिवर्तित सूती स्पिंडल के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। उन्होंने आदेश के खंड 3 के अधिकारों को भी चुनौती दी है, जिसमें खराब धागे के स्पिंडल की स्थापना और काम करने के लिए कपड़ा आयुक्त की पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक है और नियमों के नियम 174 के दूसरे परंतुक के अधिकार को भी चुनौती दी है, जो अनधिकृत स्पिंडल के मालिकों को इसके तहत लाइसेंस लेने से रोकता है। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता ने वस्त्र आयुक्त के दिनांक 13 मार्च, 1973 के आदेश (प्रतिलिपि अनुलग्नक 'डी', उनके अनधिकृत स्पिंडल को नियमित करने से इनकार करते हुए और उन्हें प्रेस नोट (प्रतिलिपि अनुलग्नक 'बी') के अनुसार उन्हें नियमित करने का निर्देश देने के लिए एक उचित रिट के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने आगे प्रार्थना की है कि आबकारी अधिकारियों को अनधिकृत स्पिंडल के गैर-नियमित होने के आधार पर नियमों के नियम 174 के तहत उन्हें जारी किए गए एल4 लाइसेंस को रद्द करने से रोका जाए।

(5) सभी रिट-याचिकाकर्ताओं ने इसी तरह सबसे खराब धागे के निर्माण में सक्षम अनधिकृत परिवर्तित सूती स्पिंडल स्थापित किए थे और 1974 के सीडब्ल्यूपी संख्या 743 और 4380 में याचिकाकर्ताओं को छोड़कर प्रेस नोट (अनुलग्नक 'बी') के अनुसरण में नियमितीकरण के लिए आवेदन किया था। कपड़ा आयुक्त ने उनकी प्रार्थनाओं को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उनके द्वारा स्थापित अनधिकृत स्पिंडल परिवर्तित सूती स्पिंडल थे न कि मूल खराब धागे वाले स्पिंडल।

(6) रिट याचिकाओं को एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा गया था, जिन्होंने 27 फरवरी, 1974 के आदेश के माध्यम से उन्हें एक खंड पीठ को संदर्भित किया क्योंकि आदेश के खंड 3 के अधिकारों के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु बड़ी संख्या में मामलों में उत्पन्न होने की संभावना है। इन्हीं परिस्थितियों में रिट याचिकाएं हमारे सामने आई हैं।

(7) प्रत्यर्थियों ने अपने लिखित बयानों में इस बात से इनकार किया कि याचिकाकर्ता प्रेस नोट के तहत स्पिंडल के नियमितीकरण के लाभ के हकदार हैं क्योंकि वे परिवर्तित सूती स्पिंडल हैं जिनका उपयोग खराब धागे के निर्माण के लिए किया जा रहा है और मूल खराब स्पिंडल नहीं हैं। उनके अनुसार, आदेश का खंड 3 और नियमों के नियम 174 का दूसरा परंतुक अधिकार से बाहर नहीं है।

(8) विचार के लिए जो बिंदु सामने आते हैं वे हैं:- 1. क्या याचिकाकर्ता प्रेस नोट अनुलग्नक 'बी' के संदर्भ में अपने अनधिकृत परिवर्तित सूती स्पिंडल को नियमित करने के हकदार हैं?

2. क्या आदेश का खंड 3 संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (छ) के अधिकार से बाहर है?

3. क्या नियमों के नियम 174 का दूसरा परंतुक केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 और संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (छ) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है?

(9) 1972 के सी डब्ल्यूपी नंबर 3605 और 3606, 2039, 2231, 2498, 249, 2555, 256, 2724, 2877, 3436, 3440, 3791 और 1973 के 3835, 1974 के 362 और 1784, 763, 1609, 1957, 6320, 6321, 6631, 7269, 7270 और 1975 के 7312 में याचिकाकर्ता ने नियमों के नियम 174 के अधिकारों को चुनौती नहीं दी है। इस कानूनी बिंदु पर तर्क देने की अनुमति दी गई थी क्योंकि इसे अन्य संबंधित रिट याचिकाओं में उठाया गया है जिन्हें इस आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है। 1974 के सी डब्ल्यूपी संख्या 743 और 4380 में याचिकाकर्ताओं ने प्रेस नोट के तहत नियमितीकरण के लिए आवेदन किया था और उन्होंने केवल आदेश के खंड 3 और नियमों के नियम 174 के दूसरे परंतुक के अधिकारों को चुनौती दी है।

(10) प्रेस नोट अनुलग्नक 'ख' आदेश के खंड 3 से सीधे जुड़ा हुआ है। इसलिए, प्रेस नोट के निहितार्थ की उचित समझ के लिए आदेश के खंड 3 की विस्तार से जांच करना आवश्यक होगा। खंड 3 (1) में इन याचिकाओं के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक प्रावधान है और यह पढ़ता है: -

"3 (1) कोई भी व्यक्ति, वस्त्र आयुक्त की लिखित पूर्व अनुमति के अलावा, बिजली द्वारा काम किए गए किसी भी स्पिंडल का अधिग्रहण या स्थापना या बिक्री या अन्यथा निपटान या स्थान में परिवर्तन नहीं करेगा और इसका उपयोग ऊनी धागे के निर्माण के उद्देश्य से नहीं करेगा।

(11) स्पिंडल के निर्माता सूती धागे के निर्माण के लिए सूती स्पिंडल और सबसे खराब ऊनी धागे के निर्माण के लिए सबसे खराब स्पिंडल बनाते हैं। कॉटन स्पिंडल और वस्टर्ड स्पिंडल के विनिर्देश और घटक अलग-अलग हैं। सूती स्पिंडल को ऊनी खराब धागे के उत्पादन के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है। एक गिल बॉक्स सबसे खराब स्पिंडल का एक आवश्यक घटक है और यह एक कपास स्पिंडल में आवश्यक नहीं है। चैम्बर्स एनसाइक्लोपीडिया, खंड 13, पृष्ठ 94 पर कताई प्रक्रियाओं का विवरण देता है। सबसे खराब के साथ संबंधित पैरा में लिखा है: "वस्टर्ड: - (as wool), 2, तैयारी, कंधी और शीर्ष परिष्करण द्वारा 'शीर्ष' या स्लिवर का गठन, 3, गिल्स और स्पिंडल ड्रॉबॉक्स या साही ड्रॉबॉक्स द्वारा ड्राइंग; 4, फ्लेयर, रिंग या कैप कताई (लंबी ऊन के लिए) या सबसे खराब खच्चर (छोटी ऊन के लिए)

दूसरा पैरा जो कपास से संबंधित है: "कपास-1 गांठ तोड़ना, मिश्रण करना और खोलना (स्कचिंग) 2, कार्डिंग और कंबिंग। 3, गति फ्रेम के माध्यम से ड्राइंग और मार्ग-स्लबिंग, मध्यवर्ती और रोविंग 4, खच्चरों या रिंग फ्रेम पर कताई।

यह स्पष्ट है कि एक गिल जो स्पिंडल का एक घटक है, स्पिंडल में ऊनी सबसे खराब धागा बनाने के लिए आवश्यक है, न कि सूती धागे के रिसाव के लिए स्पिंडल में। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि सबसे खराब तकिया में भी एक गिल आवश्यक नहीं है और इसे एक साही ड्रॉबॉक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है और ऐसा चैंबर्स एनसाइक्लोपीडिया में "सबसे खराब" शीर्षक के तहत कहा गया है। ऐसी बात नहीं है। चैंबर्स एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, एक खराब स्पिंडल में एक गिल और एक स्पिंडल ड्रॉबॉक्स आवश्यक है और एक साही ड्रॉबॉक्स स्पिंडल ड्रॉबॉक्स का विकल्प है न कि एक गिल। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के क्रमशः खंड 23 और 6 में दिए गए सबसे खराब कताई और सूती कताई का एक तुलनात्मक अध्ययन भी इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है।

(12) आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) के तहत, बिजली द्वारा काम किए गए किसी भी स्पिंडल को प्राप्त करने, स्थापित करने या बेचने या अन्यथा निपटाने के लिए और खराब धागे सहित ऊनी धागे के निर्माण के लिए स्पिंडल को काम करने के लिए कपड़ा आयुक्त की लिखित अनुमति आवश्यक है। इस प्रावधान का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय है। क्या कपड़ा आयुक्त आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) के तहत परिवर्तित सूती स्पिंडल को सबसे खराब धागे के निर्माण की अनुमति दे सकता है? इस प्रश्न का उत्तर प्रेस नोट, अनुलग्नक 'बी' के निहितार्थ को समझने में काफी मदद करेगा। प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह ने बहस के दौरान एक स्तर पर यह कठोर रुख अपनाने की कोशिश की कि आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) के तहत कपड़ा आयुक्त केवल मूल खराब स्पिंडल के संबंध में अनुमति दे सकता है और यह कि उसके पास खराब धागे का उत्पादन करने वाले परिवर्तित सूती स्पिंडल के लिए ऐसी अनुमति देने की कोई योग्यता नहीं थी। हालाँकि, उन्होंने अपने रुख को संशोधित किया (और ठीक ही किया) और कहा कि कपड़ा आयुक्त संभवतः परिवर्तित सूती स्पिंडल के लिए आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) के तहत अनुमति दे सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि वे ऊनी खराब धागे का निर्माण करने में सक्षम हैं। यह बहुत हद तक स्पष्ट है कि आदेश का खंड 3 (1) केवल मूल खराब स्पिंडल तक ही सीमित नहीं है। ऑर्डर सबसे खराब धागे के निर्माण में सक्षम मूल सबसे खराब स्पिंडल या परिवर्तित सूती स्पिंडल के बारे में चुप है। जैसा कि आदेश ऊनी कपड़ों से संबंधित है, खंड (3) के उप-खंड (1) के तहत 'स्पिंडल' शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से सबसे खराब धागे सहित ऊनी धागे का निर्माण करने में सक्षम होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस उपखंड में परिवर्तित सूती स्पिंडल भी शामिल होंगे जो सबसे खराब धागे का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। इसलिए, कपड़ा आयुक्त आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) के तहत बिजली निर्माण ऊनी खराब धागे द्वारा काम किए जाने वाले किसी भी स्पिंडल के लिए अनुमति देने के लिए सक्षम है, चाहे वह मूल खराब धागे वाला स्पिंडल हो या खराब धागे के निर्माण में सक्षम परिवर्तित सूती स्पिंडल हो।

(13) याचिकाकर्ता ने आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) के उल्लंघन में कपड़ा आयुक्त की अपेक्षित अनुमति के बिना सबसे खराब धागे के निर्माण के लिए पावर स्पिंडल स्थापित किए। स्पिंडल की स्थापना और उनका काम अनधिकृत था। वर्स्टेड यार्न एक उत्पाद से हटाने योग्य वस्तु है और इसका निर्माण नियमों के नियम 174 के अंतर्गत आता है जिसके तहत इसके निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। केन्द्र सरकार (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने 5 जून, 1971 की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 918 द्वारा नियमों के नियम 174 के दूसरे परन्तुक को प्रतिस्थापित किया है, जिसमें लिखा है: "बशर्ते कि किसी आवेदक को सूती कपड़े, या रेयॉन या कृत्रिम रेशम के कपड़े, या ऊनी धागे, या ऊनी कपड़े, या रेशम के कपड़े के निर्माण के लिए कोई लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास ऐसे सूती कपड़े, या रेयॉन या कृत्रिम रेशम के कपड़े, या ऊनी धागे, या ऊनी कपड़े या रेशम के कपड़े, जैसा भी मामला हो, की स्थापना और काम करने के लिए कपड़ा आयुक्त की लिखित अनुमति न हो।

केन्द्र सरकार ने 30 अगस्त, 1975 की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 2297 के माध्यम से दूसरे परन्तुक में और संशोधन किया और संशोधन के बाद यह परन्तुक इस प्रकार है:- "बशर्ते कि सूती कपड़े, या रेयॉन या कृत्रिम रेशम के कपड़े, या ऊनी धागे (ऊन मिश्रित धागे सहित) या ऊनी कपड़े या रेशम के कपड़े के निर्माण के लिए कोई लाइसेंस किसी आवेदक को तब तक नहीं दिया जाएगा या नवीनीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह कपड़ों (खराब, ऊनी या घटिया) या पावरलूम की स्थापना और काम करने के लिए कपड़ा आयुक्त की लिखित अनुमति नहीं रखता है या

ऐसे सूती कपड़े या रेयॉन या कृत्रिम रेशम के कपड़े, या ऊनी धागे, या ऊनी कपड़े या रेशम के कपड़े दोनों के निर्माण के लिए। जैसा कि मामला हो सकता है "।

दूसरा परंतुक, जैसा कि 1971 में संशोधित किया गया था, लाइसेंस के 'अनुदान' से संबंधित था, जबकि-1975 में किए गए संशोधन द्वारा, उसमें लाइसेंस का 'नवीकरण' भी जोड़ा गया था। 1975 में संशोधन, स्पष्ट रूप से इस बात को शामिल करने या स्पष्ट करने के लिए किया गया था कि नियमों के नियम 174 के तहत लाइसेंस देने और नवीनीकरण दोनों के लिए कपड़ा आयुक्त की लिखित अनुमति लेना आवश्यक था। 5 जून, 1971 की अधिसूचना द्वारा संशोधित दूसरे परंतुक से याचिकाकर्ताओं जैसे पक्षों के लिए कठिनाई पैदा होने की संभावना थी, जिन्होंने अनधिकृत स्पिंडल लगाए थे। कपड़ा आयुक्त ने संभवतः इस तरह की आसन्न कठिनाई को कम करने के लिए 17 फरवरी, 1971 को प्रेस नोट, अनुलग्नक 'बी' जारी किया। इस प्रेस नोट में लिखा है:

प्रेस नोट

अप्रचलित सबसे खराब स्पिनल्स

1. सबसे खराब तकियों की स्थापना ऊनी वस्त्र (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण आदेश, 1962 के खंड 3 (1) द्वारा विनियमित है। कपड़ा आयुक्त की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति खराब धागे के निर्माण के लिए उपयोग किए गए किसी भी स्पिंडल का अधिग्रहण या स्थापना या बिक्री या अन्यथा निपटान नहीं कर सकता है।

2. कपड़ा आयुक्त से अनुमति प्राप्त किए बिना खराब स्पिंडल की स्थापना उपरोक्त नियंत्रण आदेश के खंड 8 (1) का उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1965 के तहत ऐसे स्पिंडल के मालिकों पर मुकदमा चलाने का प्रश्न 5 सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद निर्णय लिया है कि नीचे निर्दिष्ट कुछ शर्तों के अधीन कपड़ा आयुक्त से औपचारिक परमिट जारी करके अनधिकृत खराब स्पिंडल को नियमित करके एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

3. तदनुसार, निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

(i) सभी अनधिकृत खराब स्पिंडल जो 17 फरवरी, 1971 को या उससे पहले प्राप्त किए गए, स्थापित किए गए और काम किए गए हैं, और केंद्रीय आबकारी अधिकारियों से वैध एल 4 लाइसेंस के साथ काम कर रहे हैं और सबसे खराब टैरिफ पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया है, उन्हें कपड़ा आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किए गए आवेदन पर परमिट जारी करके नियमित किया जाएगा, बशर्त कि स्पिंडल में बैक प्रोसेसिंग के लिए गिल बॉक्स हों। निर्धारित प्रपत्र की एक प्रति या तो वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों से या वस्त्र आयुक्त, बॉम्बे के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(ii) आवेदक को स्पिंडल और गिल बॉक्स की वास्तविक स्थापना और भौतिक कार्यप्रणाली के बारे में वस्त्र आयुक्त को संतुष्ट करना होगा।

(iii) कपड़ा आयुक्त, बॉम्बे के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 1971 है।

(iv) इस प्रकार नियमित किए गए सबसे खराब स्पिंडल की बिक्री के लिए किसी भी आवेदन पर कपड़ा आयुक्त द्वारा परमिट जारी करने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(v) नियमित रूप से खराब स्पिंडल अधिकार के रूप में आयातित कच्चे ऊन के कोटा के हकदार नहीं होंगे।

4. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ मूल में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य होंगे:

(i) फॉर्म एल 4 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस।

(ii) खराब उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के संबंध में साक्ष्य।

(iii) खराब धागे पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के संबंध में साक्ष्य।

(iv) 17 फरवरी, 1971 को सबसे खराब स्पिंडल और गिल बॉक्स की वास्तविक संख्या और स्थापना और भौतिक कार्य के बारे में साक्ष्य।

5. भविष्य में खराब स्पिंडल की किसी भी अनधिकृत स्थापना को माफ नहीं किया जाएगा।

1974 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 743 और 4380 को छोड़कर याचिकाकर्ताओं ने निर्धारित अवधि के भीतर प्रेस नोट के तहत अपने अनधिकृत स्पिंडल को नियमित करने के लिए आवेदन किया। एक अध्ययन दल ने कारखानों का दौरा किया और अंततः कपड़ा आयुक्त ने याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि वे प्रेस नोट के संदर्भ में नियमितीकरण के लिए योग्य नहीं हैं। 1973 के सी. डब्ल्यू. 2498 में याचिकाकर्ता को दिनांक 13 मार्च, 1973 को भेजे गए संचार (अनुलग्नक 'डी' की प्रति) में उन्हें अनधिकृत स्पिंडल के नियमितीकरण को अस्वीकार करने के निर्णय के बारे में सूचित करते हुए कहा गया है: "उप: 17 फरवरी, 1971 के प्रेस-नोट के अनुसार अनधिकृत खराब स्पिंडल का नियमितीकरण।

संदर्भ लें आपका आवेदन दिनांक 26 फरवरी, 1971 का है।

सज्जनों,

उपरोक्त संबंध में आपकी इकाई का मौके पर निरीक्षण करने के बाद, यह देखा गया कि आपके पास 2212 सूती स्पिंडल हैं जिन्हें खराब धागे के निर्माण में परिवर्तित किया गया है। चूंकि ऊपर उल्लिखित प्रेस-नोट केवल अनधिकृत खराब स्पिंडल के नियमितीकरण के लिए था, इसलिए कपास से परिवर्तित स्पिंडल नियमितीकरण के लिए योग्य नहीं हैं। इसलिए आपका आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

कपड़ा आयुक्त ने अनधिकृत स्पिंडल के नियमितीकरण को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि जिन स्पिंडल को नियमित करने की मांग की गई है, वे परिवर्तित सूती स्पिंडल हैं जो सबसे खराब धागे का निर्माण करते हैं और प्रेस नोट ऐसे स्पिंडल पर लागू नहीं होता है। इसलिए विचार करने की बात यह है कि क्या प्रेस नोट विशेष रूप से मूल सबसे खराब स्पिंडल पर लागू होता है या यह सबसे खराब धागे के निर्माण में परिवर्तित सूती स्पिंडल पर भी लागू होता है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि आदेश के खंड (3) के उपखंड (1) जैसे प्रेस नोट सबसे खराब धागे को कटाई करने में सक्षम सभी स्पिंडल पर लागू होता है, भले ही स्पिंडल मूल रूप से सबसे खराब स्पिंडल था या यह कॉन-परिवर्तित कपास स्पिंडल था। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने इसके विपरीत तर्क दिया है कि कपड़ा आयुक्त ने नियमित करने की सुविधा को केवल मूल खराब स्पिंडल तक बढ़ाने का फैसला किया था।

(14) प्रेस नोट आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) में निहित प्रावधान की पुनरावृत्ति के साथ शुरू होता है कि कोई भी व्यक्ति कपड़ा आयुक्त की लिखित पूर्व अनुमति के बिना खराब धागे के निर्माण के लिए उपयोग किए गए किसी भी स्पिंडल का अधिग्रहण या स्थापना या बिक्री या अन्यथा निपटान नहीं कर सकता है। इस तरह के स्पिंडल को सबसे खराब स्पिंडल कहा गया है। "वस्टेड स्पिंडल" शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यह शब्द प्रेस नोट में स्पिंडल के लिए गढ़ा गया है जो बिजली द्वारा काम करते हैं और सबसे खराब धागे के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि प्रेस नोट में प्रयुक्त "खराब तकला" शब्द आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) में प्रयुक्त "तकला" शब्द का पर्याय है।

(15) प्रेस नोट के पैरा 3 (i) में यह विशेष रूप से कहा गया है कि यह ऐसे स्पिंडल पर लागू होगा जिनमें बैंक प्रोसेसिंग के लिए गिल बॉक्स हैं। इसका मतलब है कि बिना गिल बॉक्स के स्पिंडल प्रेस नोट के दायरे से बाहर होंगे और इसके मालिकों को उनके नियमितीकरण के लिए आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह पहले माना गया है कि एक गिल बॉक्स कपास तकला का एक आवश्यक घटक नहीं है, लेकिन यह एक खराब तकला का है। इसलिए,

स्पिंडल के निर्माता अनिवार्य रूप से एक मूल खराब स्पिंडल में एक गिल बॉक्स प्रदान करेंगे। यदि प्रेस नोट का इरादा इसे केवल मूल खराब स्पिंडल पर लागू करना था, तो एक विशिष्ट शर्त क्यों रखी गई थी कि नियमित करने के लिए पात्र बनने के लिए स्पिंडल में एक गिल बॉक्स होना चाहिए। यह शर्त प्रेस नोट को आदेश के खंड 3 के उपखंड (i) के बराबर लाती है जो मूल सबसे खराब स्पिंडल और सबसे खराब धागे के निर्माण में परिवर्तित सूती स्पिंडल दोनों पर लागू होती है। इस प्रकार यह अनुमान लगाना उचित होगा कि एक गिल बॉक्स के साथ परिवर्तित सूती स्पिंडल को भी प्रेस नोट द्वारा कवर करने का इरादा था क्योंकि वे सबसे खराब धागे का उत्पादन कर सकते थे। प्रेस नोट के पैरा 3 (ii) में आगे कहा गया है कि आवेदक को स्पिंडल और गिल बॉक्स की वास्तविक स्थापना और भौतिक कार्य के बारे में वस्त्र आयुक्त को संतुष्ट करना होगा और पैरा 4 के तहत, 17 फरवरी, 1971 को सबसे खराब स्पिंडल और गिल बॉक्स की वास्तविक संख्या और स्थापना और भौतिक कार्य के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। प्रेस नोट का पाठ और सार इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि इसका उद्देश्य नियमित करने के लिए एक गिल बॉक्स के साथ परिवर्तित सूती स्पिंडल को बाहर करना नहीं था। वस्त्र आयुक्त, इसलिए, याचिकाकर्ताओं के सबसे खराब धागे का निर्माण करने वाले अनधिकृत परिवर्तित सूती स्पिंडल को इस आधार पर नियमित करने से इनकार नहीं कर सकता था कि वे मूल रूप से सबसे खराब स्पिंडल नहीं थे।

(16) प्रत्यर्थी के विद्वत वकील ने सीमा शुल्क मद्रास के कलेक्टर बनाम के. गंगा सेट्टी, (1) का हवाला दिया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह मुख्य रूप से आयात नियंत्रण प्राधिकरणों को टैरिफ अनुसूची में शीर्ष या प्रविष्टि निर्धारित करने के लिए है जिसके तहत कोई विशेष वस्तु गिरती है। यदि ऐसा करने में, इन अधिकारियों ने एक ऐसे निर्माण को अपनाया जिसे कोई उचित व्यक्ति अपना नहीं सकता था, अर्थात् यदि निर्माण विकृत है, तो यह एक ऐसा मामला है जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि दो निर्माण थे जो एक प्रविष्टि को उचित रूप से सहन कर सकते थे, और उनमें से एक जो राजस्व के पक्ष में था, को अपनाया गया था, तो न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है केवल इसलिए हस्तक्षेप करना कि विषय के लिए अनुकूल दूसरी व्याख्या न्यायालय में अपील करती है क्योंकि इसे अपनाना बेहतर है। एक अन्य प्राधिकरण जिसका उल्लेख किया गया है, वह है दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम आर. आर. गुप्ता और अन्य (2) जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि दो समान रूप से मान्य विचार संभव हैं, इसलिए विशेषज्ञ द्वारा लिया गया विचार अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष और अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रबल होगा। इन अधिकारियों पर यह प्रचार करने के लिए दबाव डाला गया है कि चूंकि कपड़ा विशेषज्ञों ने परिवर्तित सूती स्पिंडल पर प्रेस नोट लागू करने से इनकार कर दिया है, इसलिए उच्च न्यायालय को इसके विपरीत अपनी राय नहीं लगानी चाहिए। हमारे विचार में ये अधिकारी उत्तरदाताओं के लिए कोई लाभ नहीं लाते हैं। यह पाया गया है कि आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) के तहत, वस्त्र आयुक्त इस आधार पर अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता था कि स्पिंडल मूल रूप से खराब स्पिंडल निर्मित नहीं थे। प्रेस नोट में स्पष्ट रूप से सबसे खराब धागे के निर्माण के लिए अनधिकृत रूप से परिवर्तित सूती स्पिंडल को नियमित करने की परिकल्पना की गई थी। कपड़ा अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इसके विपरीत लिया गया दृष्टिकोण कि प्रेस नोट सबसे खराब धागे के निर्माण में परिवर्तित सूती स्पिंडल पर लागू नहीं होता है, न केवल गलत है, बल्कि पूरी तरह से विकृत है। सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम के. गंगा सेट्टी (उपरोक्त, इसलिए, लागू होगा और इस प्रकार न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रेस नोट दो समान रूप से मान्य विचारों को स्वीकार नहीं करता है, दिल्ली क्लॉथ में निर्धारित नियम और जनरल मिल का मामला (ऊपर, लागू नहीं होगा।

(17) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने अनुलग्नक '1' पर जोर दिया है जिसमें 'खराब स्पिंडल' और 'कपास परिवर्तित स्पिंडल' के बीच अंतर के तकनीकी निहितार्थ विस्तृत हैं। इस तकनीकी राय के लेखक का पता नहीं है। इस राय के पैरा नंबर 2 में, यह उल्लेख किया गया है कि एक गिल बॉक्स खराब स्पिंडल का एक हिस्सा है। इस अनुलग्नक का पैरा संख्या 4, 5 और 6, जिसे उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा दबाया गया है, पढ़ता है:- "4. जब सबसे खराब स्पिंडल के अनधिकृत मालिकों से नियमित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, तो यह केवल मूल सबसे खराब रिंग फ्रेम थे जो विशेष रूप से सबसे खराब याम कताई के उद्देश्य से थे जिन्हें नियमित करने का इरादा था। जब हम 'कॉटन कन्वर्टेड स्पिंडल' कहते हैं, तो हमारा मतलब है कि कताई के फ्रेम मूल रूप से



सूती धागे को कटाई करने के लिए थे और इस तरह बेचे जाते थे, लेकिन जिन्हें बाद में ऊनी धागे या खराब धागे के कटाई के लिए संशोधित किया गया था। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कच्चे माल का उचित उपयोग किया जाए, यह वांछनीय माना जाता था कि केवल खराब रिंग फ्रेम ही नियमितीकरण के हकदार थे। सरकार का इरादा उन स्पिंडल को नियमित करना था जो केवल खराब कच्चे माल पर काम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि, मेरिनो ऊन का आयात किया जाता है और विदेशी मुद्रा की उपलब्धता की कमी के कारण इसकी आपूर्ति हमेशा कम होती है। इसलिए, एक स्पिंडल को नियमित करने का कोई मतलब नहीं है जो कपास पर सुविधाजनक और आर्थिक रूप से काम कर सकता है क्योंकि उसे उस उद्देश्य के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया था।

5. यह कहा जाना चाहिए कि चूंकि मशीनों का मूल उद्देश्य फाइबर के स्ट्रैंड में ट्विस्ट की शुरुआत है, इसलिए कुछ संशोधनों के साथ फाइबर के स्ट्रैंड से यार्न प्राप्त करने के लिए एक फ्रेम का उपयोग करना संभव हो सकता है, जिसके लिए यह विशेष फ्रेम मूल रूप से फ्रेम के निर्माण के समय नहीं था। लेकिन इन संशोधनों को तकनीकी रूप से सफल नहीं माना जा सकता है क्योंकि मूल फ्रेम को एक विशेष फाइबर से धागे के कुशल उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है। एक कटाई फ्रेम को दूसरे प्रकार के कटाई फ्रेम में परिवर्तित करते समय, फिर भी उन्हें एक विशेष काम करने के लिए केवल 'परिवर्तित फ्रेम' कहा जा सकता है जो वे मूल रूप से करने के लिए नहीं थे।

6. यह सर्वविदित तथ्य है कि कच्चा ऊन एक महंगा रेशा है और सरकार का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि इस महंगे रेशे का उपयोग बेहतर प्राप्ति के लिए सबसे कुशल तरीके से किया जाए अन्यथा इसका मतलब विदेशी मुद्रा की प्रत्यक्ष बर्बादी होगी।

(18) प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि एक स्पिंडल को नियमित करने का कोई मतलब नहीं है जो कपास पर सुविधाजनक और आर्थिक रूप से काम कर सकता है क्योंकि इसे उस उद्देश्य के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया था और कपास परिवर्तित स्पिंडल में किए गए संशोधनों को तकनीकी रूप से सफल नहीं माना जा सकता है और आगे सरकार मूल खराब स्पिंडल के नियमितकरण पर जोर देकर बेहतर प्राप्ति के लिए सबसे कुशल तरीके से महंगे कच्चे ऊन का उपयोग करने का इरादा रखती है और अन्यथा ऐसा करने का मतलब कच्चे ऊन के आयात में खर्च की गई विदेशी मुद्रा का प्रत्यक्ष अपव्यय होगा। हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। ऊपर दिए गए हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, विशेषज्ञ राय अनुलग्नक '1' पूरी तरह से अनुपयुक्त और गलत है। सबसे खराब याम के निर्माण में अनधिकृत रूप से परिवर्तित सूती स्पिंडल को नियमित करने का निर्णय प्रेस नोट में देने के बाद, कपड़ा आयुक्त को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि प्रेस नोट का उद्देश्य ऐसे स्पिंडल पर लागू होना नहीं था या सबसे खराब धागे के निर्माण के लिए उनका उपयोग करना किफायती और सुविधाजनक नहीं होगा। और आयातित सामग्री का कथित दुरुपयोग एक अतिरिक्त कारण के लिए अप्रासंगिक है कि यह विशेष रूप से प्रेस नोट के पैरा 3 (5) में प्रदान किया गया है कि नियमित रूप से खराब स्पिंडल अधिकार के रूप में आयातित कच्चे ऊन के कोटा के हकदार नहीं होंगे।

(19) वस्त्र आयुक्त ने प्रेस नोट, अनुलग्नक 'ख' में अनधिकृत खराब स्पिंडल को नियमित करने के लिए शर्तें रखी हैं। वह परिवर्तित सूती स्पिंडल के नियमितीकरण को अस्वीकार कर सकते थे यदि इस तरह की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जाता था, लेकिन इस आधार पर नहीं कि सबसे खराब धागे का निर्माण करने वाले परिवर्तित सूती स्पिंडल मूल सबसे खराब स्पिंडल नहीं हैं।

(20) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, बिंदु संख्या 1 का उत्तर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सकारात्मक रूप से दिया गया है।

(21) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि आदेश के खंड 3 का आक्षेपित उपखंड (1) वस्त्र आयुक्त द्वारा इसके तहत शक्ति के प्रयोग के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं करता है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद

14 और 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रचार किया है कि आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी किया गया है। अधिनियम की प्रस्तावना और उसकी धारा 3 में, आक्षेपित उपखंड के तहत वस्त्र आयुक्त द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए पर्याप्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि विवादित उपखंड की शक्ति का उपयोग कपड़ा आयुक्त द्वारा किया जा सकता है जो पूरे भारत में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं और उनके निर्णय के खिलाफ अपील भारत सरकार के पास है। इसलिए, आक्षेपित उपखंड को संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (छ) का उल्लंघनकारी नहीं माना जा सकता है।

(22) आक्षेपित उपखंड स्वयं वस्त्र आयुक्त द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं करता है। इस उपखंड के तहत प्राधिकरण का उपयोग विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कपड़ा आयुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता है जो एक उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है। आदेश के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए सक्षम "वस्त्र आयुक्त" को उसके खंड 2 (डी) में परिभाषित किया गया है और इसमें कहा गया है: "2 (डी) वस्त्र आयुक्त "का अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वस्त्र आयुक्त और इसमें एक अतिरिक्त या एक संयुक्त या एक उप वस्त्र आयुक्त, औद्योगिक सलाहकार और पदेन संयुक्त वस्त्र आयुक्त, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त ऊनी वस्त्र नियंत्रक, और कोई अन्य अधिकारी जिसे 1 केंद्र सरकार या वस्त्र आयुक्त 2 केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, इस आदेश के तहत वस्त्र आयुक्त की सभी या किसी भी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं;" आक्षेपित उपखंड के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए सक्षम 'वस्त्र आयुक्त' में अन्य अधिकारियों का एक पदानुक्रम शामिल है और किसी भी रैंक के किसी भी अधिकारी को वस्त्र आयुक्त की शक्तियां दी जा सकती हैं। यह समझा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कपड़ा आयुक्त संभवतः अपने स्तर पर सभी मामलों से नहीं निपट सकता है।

(23) नरेन्द्र कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में, (3) यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब प्रतिबंध निषेध के स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो न्यायालय द्वारा यह देखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि तर्कसंगतता की कसौटी संतुष्ट हो। प्रतिबंध जितना अधिक होगा, अदालत द्वारा कड़ी जांच की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। पंजाब राज्य और एक अन्य बनाम खान चंद में, (4) पूर्वी पंजाब चल संपत्ति (अधिग्रहण अधिनियम (1947 का 15) जांच के दायरे में था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इसने अधिकारियों को चल संपत्ति की मांग करने के लिए मनमाने अधिकार प्रदान किए थे और मांग करने की शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे। चल संपत्ति के अधिग्रहण की शक्तियों के प्रयोग के लिए दिशा-निर्देशों का पूर्ण अभाव अधिनियम की धारा 2 को दूषित करता है। अधिनियम के प्रावधान के बावजूद मनमानेपन और भेदभाव करने की शक्ति व्यापक रूप से लिखी गई है और इसलिए यह उस शरारत के दायरे में आता है जिसे रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 को तैयार किया गया था। मोहन इंडस्ट्रीज और अन्य बनाम उद्योग और वाणिज्य के उप निदेशक और अन्य पैराफिन वैक्स (आपूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण आदेश, 1972) के खंड (5) को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए निरस्त कर दिया गया था क्योंकि यह एक कार्यकारी अधिकारी को आवंटन के अनुदान या इनकार के लिए कारण देने की आवश्यकता के बिना और उसके आदेश को अपील के अधीन किए बिना आवंटन की निर्देशित और पूर्ण शक्ति प्रदान करता है।

(24) विभिन्न प्राधिकरणों का सुसंगत अनुपात वह है जहां एक पूर्ण, दिशाहीन और अनियंत्रित शक्ति प्रदान की जाती है। एक कार्यकारी प्राधिकरण पर, मनमाने तरीके से इसके प्रयोग के परिणामस्वरूप भेदभाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो इसे असंवैधानिक बना देगा। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि आक्षेपित उपखंड के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश आवश्यक वस्तु अधिनियम की प्रस्तावना और धारा 3 में निहित हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की प्रस्तावना और धारा 3 धारा 3 के तहत आदेश जारी करने के लिए कार्यपालिका के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में काम कर सकती है, लेकिन यह मानना मुश्किल है कि वे संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) के साथ अपने टकराव को बचाने के लिए विवादित उपखंड के तहत कपड़ा आयुक्त द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ण दिशानिर्देश होंगे। यह लाभ के साथ जोड़ा जा सकता है कि मूल्य निर्धारण से संबंधित आदेश के खंड 4 में और कपड़ा (पावरलूम नियंत्रण आदेश, 1956 द्वारा उत्पादन, सूती कपड़ा (नियंत्रण)

आदेश, 1948, जूट कपड़ा (नियंत्रण) आदेश, 1956 और सब्जी तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 जैसे विभिन्न अन्य आदेशों में दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं। यदि प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील का तर्क प्रबल होना था, तो किसी भी आदेश के किसी भी खंड के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने की शायद ही कोई आवश्यकता थी। इसलिए, हम उत्तरदाताओं के विद्वान वकील से सहमत होने में असमर्थ हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की प्रस्तावना और धारा 3 आक्षेपित उपखंड के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए वस्त्र आयुक्त के लिए दिशानिर्देशों के रूप में काम करेगी।

(25) प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आक्षेपित उपखंड के तहत वस्त्र आयुक्त के आदेश को भारत सरकार के समक्ष अपील में चुनौती दी जा सकती है, उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति को मनमाना और संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने च टीका रामजी और अन्य पर निर्भरता रखी है, वगैरह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (6). इस प्राधिकरण का अनुपात 1 है जो वर्तमान मामलों के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्राधिकरण में, यू पी गन्ना के तहत गन्ना आयुक्त को प्रदत्त अधिकार की संवैधानिक वैधता (आपूर्ति और खरीद विनियमन अधिनियम, 1941 को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण चुनौती दी गई थी। गन्ना आयुक्त का अधिकार उस अधिनियम की धारा 15 और यू पी गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन नियम, 1954, अधिनियम की धारा 29 (2) द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए यू पी सरकार द्वारा बनाए गए यू पी गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन नियम, 1954) के नियम 22 में निहित था। इस पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह तर्क कि आक्षेपित अधिनियम अनुच्छेद 14 के अधीन गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि गन्ना आयुक्त को बहुत व्यापक शक्तियां दी गई थीं, जिनका उपयोग भेदभावपूर्ण तरीके से किया जा सकता था, बिना किसी आधार के था क्योंकि आक्षेपित अधिनियम की धारा 15 के तहत उनकी शक्तियां अच्छी तरह से परिभाषित थीं और अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम एक गन्ना उत्पादक या एक गन्ना उत्पादक सहकारी समिति या एक कारखाने के अधिभोगकर्ता को उनके द्वारा पारित आदेश के खिलाफ राज्य सरकार को अपील करने का अधिकार देते थे और यह उन शक्तियों के मनमाने प्रयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा थी। वर्तमान मामलों में, आक्षेपित उपखंड के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। केवल आक्षेपित उपखंड के तहत कपड़ा आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान वर्तमान मामले को च टीका रामजी के मामले (उपर्युक्त) के बराबर नहीं लाएगा। इसलिए, प्रतिवादी अपने लाभ के लिए इस सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार पर दबाव नहीं डाल सकते हैं।

(26) प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया एक अन्य बिंदु यह है कि विवादित उपखंड के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कपड़ा आयुक्त है जो पूरे भारत में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला एक उच्च पदस्थ अधिकारी है और इसलिए, इसे दिशानिर्देशों के अभाव के लिए असंवैधानिक के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार और अन्य (7), जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी आदेशों के अधीन शक्ति उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकती है, ऐसे अधिकारियों द्वारा इसके दुरुपयोग को आसानी से नहीं माना जा सकता है। यह प्राधिकरण फिर से वर्तमान मामलों के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि आक्षेपित उपखंड के तहत शक्ति वस्त्र आयुक्त द्वारा और आदेश में दी गई वस्त्र आयुक्त की परिभाषा में उल्लिखित अन्य अधिकारियों के पदानुक्रम द्वारा भी प्रयोग की जाती है। कपड़ा आयुक्त की शक्तियां केंद्र सरकार या कपड़ा आयुक्त द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जा सकती हैं। इसलिए, विद्वान वकील, विवादित उपखंड को संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाने के लिए इस तर्क को वैध रूप से दबा नहीं सकता है।

(27) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित उपखंड में तकनीकी विशेषज्ञता शामिल है जो दिशानिर्देशों द्वारा सीमित होने को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम इस तर्क की योग्यता की सराहना कर सकते हैं। आक्षेपित उपखंड कपड़ा आयुक्त को बिजली द्वारा काम किए गए स्पिंडल के अधिग्रहण, स्थापना,

बिक्री या स्थान परिवर्तन और ऊनी धागे के निर्माण के लिए उनके उपयोग के मामले में अनुमति देने या अस्वीकार करने की पूर्ण और मनमाना शक्ति देता है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि इस तरह की शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। उसे अपने निर्णय के समर्थन में कारण दर्ज करने का आदेश नहीं दिया गया है। दिशानिर्देशों के अभाव में कपड़ा आयुक्त द्वारा एक अनुमेय गैर-भाषी आदेश शायद ही अपील को उनकी मनमानेपन और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघनकारी भेदभाव करने की शक्ति पर एक प्रभावी जांच बना देगा।

(28) प्रत्यर्थियों के विद्वत वकील ने आग्रह किया है कि आक्षेपित उपखंड के अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा पारित मनमाने आदेश को निरस्त किया जा सकता है, लेकिन यह आशंका कि ऐसे मनमाने आदेश उसके द्वारा पारित किए जा सकते हैं, उपखंड को असंवैधानिक नहीं बनाएगा क्योंकि दिशानिर्देशों की उपस्थिति में भी वस्त्र आयुक्त द्वारा कुछ विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाएगा। विवाद फिर से बेमानी है। संवैधानिक वैधता की जांच करते समय यदि आक्षेपित उपखंड है, तो वास्तविक परीक्षा कपड़ा आयुक्त की मनमाना और भेदभावपूर्ण आदेश पारित करने की संभावित शक्ति है। यह अभिनिर्धारित करना गलत होगा कि केवल इसलिए कि यदि एक मनमाना आदेश पारित किया जाता है तो उसे निरस्त किया जा सकता है, न्यायालय विवादित उपखंड की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं कर सकता है। हमारे विचार में, आक्षेपित उपखंड संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (छ) का उल्लंघन करता है और इसके अधिकार से बाहर है क्योंकि यह वस्त्र आयुक्त को निर्देशित और पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। बिंदु संख्या 2 का उत्तर सकारात्मक और फिर से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिया जाता है।

(29) यह हमें नियमों के नियम 174 के दूसरे परन्तुक के अधिकारों से संबंधित अंतिम बिंदु पर लाता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील ने तर्क दिया है कि यह परन्तुक आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) से जुड़ा हुआ है और बाद वाले को असंवैधानिक ठहराए जाने की स्थिति में, पूर्व को संदर्भ से बाहर और निष्क्रिय कर दिया जाएगा क्योंकि इससे शून्य में काम करने की उम्मीद नहीं है। प्रत्यर्थियों के विद्वत वकील ने दलीलों के दौरान (और उचित रूप से) स्वीकार किया कि यदि आक्षेपित परन्तुक आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) पर आधारित माना जाता है, तो पूर्व को असंवैधानिक ठहराए जाने की स्थिति में अप्रभावी बना दिया जाएगा। हालाँकि, उन्होंने आग्रह किया है कि उठाई गई धारणा गलत है और आक्षेपित परन्तुक अनिवार्य रूप से आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) से जुड़ा नहीं है। तर्क आगे बढ़ता है कि नियम केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम की धारा 37 के तहत बनाए गए हैं और इसकी उप-धारा (2) के खंड (5) के तहत, किसी भी उत्पाद के उत्पादन को विनियमित करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं यदि यह अधिनियम के तहत उचित लेवी और शुल्क के संग्रह के लिए आवश्यक है। आक्षेपित परन्तुक सबसे खराब धागे के उत्पादन से संबंधित है जो एक उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु है। यह वास्तव में केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम के तहत और आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) से स्वतंत्र रूप से बनाया जा सकता था और किया जा सकता था। इसलिए यह वैध बना रहेगा, भले ही आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) को असंवैधानिक ठहराया गया हो। हम इस विवाद में कोई ताकत नहीं पाते हैं। केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) का खंड (5) उत्पादन के विनियमन से संबंधित है और इसके अतिरिक्त शुल्कों के उचित उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए आवश्यक सीमा तक है, जबकि आक्षेपित परन्तुक सबसे खराब स्पिंडल की स्थापना, कार्य और स्थान परिवर्तन के लिए वस्त्र आयुक्त की लिखित अनुमति रखने से संबंधित है। यह स्पष्ट है कि आक्षेपित परन्तुक आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) के अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति पर निर्भर करता है। इसके अलावा आक्षेपित परन्तुक, यदि आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) से स्वतंत्र है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (छ) का भी उल्लंघन करता है और आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) जैसे दिशा-निर्देशों के अभाव में निरस्त किया जा सकता है। बिन्दु संख्या 3 का निर्णय तदनुसार याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किया जाता है।

(30) परिणामस्वरूप, हमने 1974 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 743 और 4380 को छोड़कर सभी याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के अनधिकृत परिवर्तित सूती स्पिंडल को विनियमित करने से इनकार करने वाले वस्त्र आयुक्त के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया। हम आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) को संविधान के अनुच्छेद 14 और 19

(1) (छ) का उल्लंघन करने वाले होने के कारण निरस्त करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नियमों के नियम 174 का दूसरा परंतुक अप्रभावी हो जाएगा। सभी रिट याचिकाओं को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के स्वीकार किया जाता है।

एन के एस

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फरीदाबाद, हरियाणा